*271. [*Transferred to the 19th December, 1991*].

Shortage of Manpower for Direct tax Collection

*272. SHRI H. HANUMANTHAPPA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the direct tax collection has suffered because of shortage of manpower at crucial points; and

(b) what steps Government propose to augment the manpower so as to increase the direct tax collection?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) In the current year, the direct tax collections between April to November have totalled up to Rs. 4692 crores, compared to only Rs. 3443 crores during the corresponding period in 1990-91, thus registering a 36.27 percent increase. This increase is attributable to the impact of additional resource mobilisation measures introduced in the last Budget as well as to higher realisation of arrears.

(b) The manpower required for tax collection purposes is assessed from time to time and necessary increases allowed as assessed. Proposals for further augmentation of the staff strength, over the present levels are now under consideration, based on the report of the Cadre review Committee.

देश में सोने की उपलब्धता में वृद्धि

*273. **श्री जे० पी० जवलि** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोने का वार्षिक उत्पादन मात्र 2 टन है जबकि जनता द्वारा इसकी अनुमानित मांग 200 से 300 टन है;

(ख) क्या मांग और पूर्ति के इस अत्यधिक अन्तर के कारण सोने की तस्करी होती है; और

(ग) यदि हां, तो सोने की मांग को अधिकारिक माध्यमों से पूरा करने के लिये क्या-क्या कदम उठाये जाने पर विचार किया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) पिछले कुछ वर्षों में सोने का वार्षिक घरेलू उत्पादन 2 टन प्रति वर्ष से कुछ अधिक रहा है। देश में सोने की मांग के संबंध में सरकार के पास कोई विश्वसनीय या वास्तविक अनुमान नहीं है।

(ख) यह अनुमान है कि मांग और पूर्ति के बीच काफी अन्तर है जिसके परिणामस्वरूप सोने की तस्करी होती है।

(ग) सरकार सोने की घरेलू मांग की पूरी तरह पूर्ति करने के लिए कोई उपाय करना आवश्यक नहीं समझती क्योंकि सोना एक आवश्यक वस्तु नहीं है। किसी भी स्थिति में, अर्थव्यवस्था तथा विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के मौजूदा हालात में पूरी तरह सरकारी माध्यम के जरिए सोने की मांग को पूरा करना व्यवहार्य नहीं होगा।

Pension Scheme for Class III and IV Employees of LIC

*274. PROF. **SAURIN BHATTACHARYA**: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether any memoranda have been received by Government regarding the introduction of Pension Scheme for Class III and IV employees of Life Insurance Corporation in lieu of employer's contribution to their C.P.F. on the lines of the Pension Scheme for employees of the Reserve Bank of India;

(b) if so, what action has been taken in this regard; and

(c) if answer to part (b) above be in negative, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Life Insurance Corporation of India has not found this feasible and also, the employees of the Life Insurance Corporation are demanding pension as a third retirement benefit. At present they are getting Gratuity and matching contribution of the employer in the Contributory Provident Fund. It has not been considered possible to accede to the demand of pension as a third benefit.

सरकार द्वारा विद्युत केन्द्र पर किया गया व्यय

*275. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या **विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन और उनकी वितरण- हानियों के सम्बन्ध में, राज्य-वार, कुल कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ख) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में इस सम्बन्ध में गुजरात में किए गये प्रयासों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) विद्युत केन्द्रों के प्रचालन एवं अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य, युटिलिटियों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों द्वारा निष्पादित किए जा रहे हैं। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र जोकि प्रत्यक्ष रूप से केन्द्र सरकार के स्वामित्व में है और जिसकी प्रबन्ध व्यवस्था राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा एजेंसी आधार पर ली जा रही है, के प्रचालन एवं अनुरक्षण हेतु निम्नानुसार निधियां जारी की गई थी :-

बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र (वास्तविक रूप से जारी निधियां)

	(करोड़ रुपये)
1990-91	319.0623
1989-90	318.3033
1988-89	246.6351

ताप विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन सुधार करने की दृष्टि से एक नवीकरण एवं आधुनिकीकरण स्कीम तथा उत्कृष्ट उत्पादकता पुरस्कार स्कीम आरम्भ की गई है।

वर्ष 1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान पारेषण एवं वितरण हानियों का राज्यवार एवं वर्षवार विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिए)** पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी होने प्रोत्साहन स्कीम भी आरम्भ की गई है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार हेतु नवीकरण एवं आधुनिकीकरण स्कीम के अन्तर्गत जारी धनराशि और प्रदान किए गए पुरस्कारों पर व्यय की गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

वर्ष	राशि (करोड़ रुपये)
1988-89	117.90
1989-90	114.15
1990-91	61.99

(ख) गुजरात राज्य के ताप विद्युत केन्द्रों को भी नवीकरण एवं आधुनिकीकरण स्कीम तथा उत्कृष्ट उत्पादन पुरस्कार स्कीम में शामिल किया गया है। इसी प्रकार, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी हेतु प्रोत्साहन स्कीम में गुजरात राज्य की पारेषण एवं वितरण प्रणाली सम्मिलित हैं।